



राजस्थान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को स्टेच्यु सर्किल, जनपथ और अन्य स्थानों को रोशनी से जगमग किया गया।

## आई.ए.एस. देथा के माफी मांगने पर अवमानना कार्रवाई समाप्त

### कोर्ट ने कहा कि आमजन की जगह खुद को रखकर देखो

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से अवमानना के मामले में दिए आदेश की पालना में आईएसएस भवानी सिंह देथा और तत्कालीन संयुक्त कॉलेज शिक्षा आयुक्त आरसी मीणा ने पेश होकर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। वहीं आईएसएस शुचि त्यागी के अवकाश पर होने के चलते उनकी ओर से माफी मांगने की जानकारी एएजी विज्ञान शाह ने अदालत के सामने रखी। इस पर अदालत ने तीनों अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश डॉ. डीसी डूडी की अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान आईएसएस देथा और आरसी मीणा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी ओर से पालना नहीं की जाती है। ऐसे में पक्षकार को अवमानना याचिका दायर करने के लिए एक बार फिर अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अदालत ने कहा कि आप आमजन की जगह खुद को रखकर सोचिए। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ और मुझे पता है कि आमजन को ऐसे मामलों में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जनता के हितों को देखते हुए अफसरों को तब तक माफी मांगने की पालना नहीं करनी चाहिए। इस पर आईएसएस देथा ने

कहा कि उनका कभी भी अदालती आदेश की अवमानना करने का आशय नहीं रहता है और वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। देथा ने अदालत को आश्चर्य किया कि भविष्य में अदालती आदेशों की समय पर पालना की जाएगी। इस दौरान दूसरे अधिकारी आरसी मीणा ने भी अदालत से माफी मांगी। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आईएसएस शुचि त्यागी बाहर होने के चलते अदालत में नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी का संदेश भिजवाया है। ऐसे में उन्हें भी अवमानना से मुक्त किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत

ने तीनों अफसरों को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता सांभर लेक में कॉलेज व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वह हरियाणा में लेक्चरर था। विभागा ने करियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए उनकी पुरानी सेवा को सेवा लाभ में नहीं जोड़ा। ऐसे में उसे बड़े हुए वेतनमान वेतनमान मिलने में डेढ़ साल की देरी हुई। इस पर डूडी की ओर दायर याचिका में एकलपीठ ने 5 मई 2022 की याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था। राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद भी विभागा ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर अदालत में अवमानना याचिका दायर हुई थी। पूर्व में अदालत की सख्ती के बाद आदेश की पालना हुई थी। इस दौरान अदालत के सामने आया कि आईएसएस देथा के खिलाफ अवमानना के 46 मामले लंबित हैं।

## गुलाबी नगरी में राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन



जयपुर। राष्ट्र सेविका समिति जयपुर विभाग का शुक्रवार को शोर्टवाड़ा में पथ संचलन निकाला। घोष वादन के साथ कदम से कदम मिलाली सेविकाएं उन्साह के साथ पथ संचलन में चल रही थी। सैकड़ों की संख्या में समिति से जुड़ी युवतियां एवं महिलाएं इसमें

शामिल थी। पथ संचालन शोर्टवाड़ा आदर्श विद्या मंदिर के खेल मैदान से प्रारंभ होकर कांटा चौराहा, कालवाड़ा रोड होते हुए मेडिकल सेंटर से पुनः खेल मैदान में आकर समाप्त हुआ। इस मार्ग में स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया।

भारत माता के जयकारों के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति मय हो गया। राष्ट्र सेविका समिति जयपुर प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुखा नवदा इन्दीराजी ने कहा कि महिलाएं परिवार की धूरी होती हैं। राष्ट्र सेविका समिति देश सेवा का संस्कार देती है।

## पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी जीए-एएजी पद पर नियुक्ति क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जयपुर पीठ में आपराधिक मामलों की पैरवी के लिए जीए-एएजी पद पर अधिवक्ता बीएन सांदू की नियुक्ति को पूर्णपीठ की 16 अप्रैल 2024 को दी सहमति के बाद भी नियुक्ति नहीं देने को गंभीर माना है। वहीं अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व अधिवक्ता सांदू से भी जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने प्रमुख विधि सचिव को निर्देश दिया है कि वे 12 अप्रैल को मूल रिकॉर्ड पेश कर बताएं कि पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी जीए-एएजी पद पर

नियुक्ति क्यों नहीं की गई। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंग लेते हुए दिए। अदालत ने कहा कि पिछले एक साल से फौजदारी केंसों का काम प्रभावित हो रहा है और इन केंसों की पैरवी में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा। यह बाढ़ ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्णपीठ की सहमति मिलने के बाद भी जीए-एएजी पद पर नियुक्ति नहीं करना अदालत की अवमानना है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एके गुप्ता की ओर से कहा कि हाईकोर्ट में लंबित फौजदारी केंसों की संख्या ज्यादा है।

## लू और तापघात से पशुओं को बचाएं : कुमावत

जयपुर। गर्मी के मौसम में लू का प्रकोप शुरू हो जाता है। ऐसे में पशुओं को भी लू से बचाना जरूरी होता है, वरना पशुधन बीमार पड़ सकता है। पशुपालन मंत्री जोगराम कुमावत ने कहा है कि प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रभाव से पशुधन को स्वस्थ रखने हेतु प्रदेश के पशुपालकों को सचेत और जागरूक करना आवश्यक है, ताकि पशुओं के रखरखाव पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु उनके द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा सकें तथा सघातों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है आगामी महीनों में तापमान बढ़ने के साथ लू और तापघात के कारण पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता पर असर पड़ सकता है।

## बजरी मामलों की जांच सीबीआई को देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, चोरी व बजरी माफियाओं से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 16 अप्रैल 2024 को दिए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को भी फिलहाल रोकने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शेखावत एसोसिएट्स की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए।

एसएलपी में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व अधिवक्ता संदीप सिंह शेखावत ने हाईकोर्ट के 16 अप्रैल, 2024 व 17 मार्च 2025 सहित अन्य आदेशों को चुनौती देते हुए कहा कि प्राथी जहाजपुर, भोलवाड़ा का पूर्व खान लीज धारक है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 मार्च को उसकी पक्षकार बनने की अर्जी खारिज कर दी है। जबकि सीबीआई ने उन्हे मामले में नोटिस जारी कर उसके खिलाफ अनुसंधान कार्रवाई करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट जब बजरी चोरी से जुड़े मामले में आरोपी की जमानत

याचिका को निस्तारित कर चुका है। तो अब मामले की सुनवाई करने और बजरी चोरी सहित इससे जुड़े अन्य केंसों की जांच सीबीआई को नहीं भेज सकता। हाईकोर्ट इस तरह से किसी अन्य जांच एजेंसी को निर्देश नहीं दे सकता और यह कानून संगत नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने वाले आदेश सहित हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए चल रही कार्रवाई को भी रोक दिया है।

## छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे एल.आई.सी. कार्यालय

जयपुर। पॉलिसीधारकों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय के अंतर्गत सभी कार्यालय 29 से 31 मार्च को छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। इन कार्यालयों में सामान्य परिचालन का कार्य भी होगा। यह भारतीय बीमा निगमक और विकास प्राधिकरण द्वारा 12 मार्च 2025 को जारी एडवाइजरी के अनुसार है।



राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के अवसर पर 30 मार्च को राजपत्रित अवकाश होने के कारण 28 मार्च को ही शपथ समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में राजस्थान दिवस के गौरवमयी अवसर पर शुक्रवार को पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. आनंद सेनरा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश के विकास, खुशहाली, आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने उपस्थित होकर विरासत भी और विकास भी की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विकास के प्रति निष्ठा के लिए संकल्पबद्ध रहकर काम करने की शपथ ली।

## गडकरी ने जैसलमेर व बाड़मेर में 1237 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी दी

जयपुर/दिल्ली। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में सकारात्मक चर्चा हुई।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-70 और राष्ट्रीय राजमार्ग-11 (कुल लंबाई 134.86 किलोमीटर) के मौजूदा कनेक्शन को मजबूत/चौड़ा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के म्याजलार-जैसलमेर खंड और मुनाबाव-तनोट के सुंदरा-म्याजलर-अंबासिंह की ढाणी रोड भाग से पक्की सड़क के साथ 2-लेन का मजबूत और चौड़ीकरण करने के लिए 1237.71 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित सरंक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग-25 और राष्ट्रीय राजमार्ग-68 के साथ संपर्क स्थापित करेगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग-70 से भी जुड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में और वृद्धि होगी। यह परियोजना महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखती है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है, जो सुरक्षा कर्मियों की सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से पहुंचने की क्षमता को बहुत बढ़ाएगी। यह परियोजना सड़क लोकप्रिय पर्यटन



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मुलाकात की।

स्थल खुरी रेत के टीलों से भी होकर गुजरेगी और इससे मार्ग के किनारे स्थित अनेक गांवों को लाभ मिलेगा, तथा क्षेत्र के समग्र विकास और संपर्क में योगदान मिलेगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया की केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान

अधिकारियों ने अवगत कराया की जयपुर, जोधपुर और उदयपुर रिंग रोड आदि की डीपीआर के आदेश अगले महीने हो जाएँगे एवं राजस्थान के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार करोड़ के कार्य वार्षिक योजना में लिए जाएँगे। इसके साथ

■ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर के काम अगले माह से शुरू होंगे

ही सीआरआईएफ में भी राजस्थान को 1500 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त भरतपुर रिंग रोड, एलिक्ट्रेड रोड, एवं ब्रज चौरासी परिक्रमा, जयपुर जोधपुर पंचपदरा रोड की डीपीआर का कार्य अगले महीने शुरू होगा। उन्होंने बताया की जयपुर सीकर रोड का कार्य तेज गति से होगा। साथ ही खादू श्याम जी रिंग रोड एवं सुविधा विकसित करने के लिए डीपीआर के कार्य आदेश जल्द दिए जाएँगे। इसके अतिरिक्त जयपुर किशनगढ़ हाईवे के सुदृढीकरण हेतु डीपीआर बनवाई जायेगी। उन्होंने बताया की एनएचआई द्वारा जयपुर दिल्ली पुराने हाईवे का कार्य जुलाई तक कर दिया जाएगा साथ ही शाहपुरा बाईपास के लिए डीपीआर के आदेश जल्द दिए जाएँगे। इसके अतिरिक्त देपुरी की नाल पर डीपीआर का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तत्पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

## आयोग में सदस्य नियुक्ति को लेकर स्टे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि नियुक्ति को लेकर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित नहीं किए जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पवन कुमार भाट्टाज की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

## सी.एस. सहित 17 को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बावजूद चोर्म तहसील की ग्राम पंचायत हाडौता में सरकारी भूमि पर भारी चारा वाहनों की पार्किंग कराने पर मुख्य सचिव, पंचायती राज आयुक्त, प्रमुख राजस्व सचिव, कलेक्टर, यातायात उपायुक्त, एएसडीएम और स्थानीय सरपंच सहित कुल 17 लोगों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और पीठ के प्रमुख जज आर.ए.राय को किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना चारा वाहनों के लिए पार्किंग का ठेका दे दिया। हाईकोर्ट ने गत 8 नवंबर को यहां पार्किंग करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा

■ अदालती आदेश के बावजूद सरकारी जमीन पर भारी वाहनों की पार्किंग का मामला

था। इसके बावजूद इस जमीन पर पार्किंग ठेकेदार से मिलीभगत कर अवैध पार्किंग कराई जा रही है। याचिका में कहा गया कि कारस्थानी अधिकारियों, पंचायती राज अधिकारियों और भू राजस्व अधिकारियों के तहत चारागाह भूमि और आम रास्ते की जमीन जमीन का अन्य प्रयोग के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। इसके अलावा अदालती रोक होने के बाद भी अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में दोषी अफसरों की अवमानना के लिए पार्किंग जारी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

## 'कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे का सदन में दिया बयान अक्षम्य'

■ सांसद सुमन का बयान सोचा समझा और पूर्ण रूप से नियोजित, यह इंडी टाइम्स की मानसिकता का द्योतक : डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल

■ 'देश का इतिहास गवाह है, कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने की आदी है'

सुमन ने जो कुछ कहा था, वो सोच समझ कर कहा था, पूर्ण होशोहवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। यह संपूर्ण इंडी टाइम्स की मानसिकता का द्योतक है। एक बार तो सदस्य के कहनुमे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इस

का मुद्दा उठाकर राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है। इन्होंने इस मामले का राजनीतिकरण किया है, यह कांग्रेस की सोचि हुई मंशा है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि डॉ. अम्बेडकर एक दलित थे, डॉ. अम्बेडकर ने 25 अप्रैल को कहा था कि चाहे जो भी हो जाए इस देश को कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। आज सदन में खरगे ने अपनी उसी मानसिकता को सिद्ध करने का कार्य किया है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी, जबकि हमारे देश के लिए संपर्क करने वालों को फांसी पर चढ़ाने के लिए समझौता किया करती थी।

## वर्ष प्रतिपदा एवं राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को वर्ष प्रतिपदा एवं राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनसे सशक्त, समर्थ, समृद्ध एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए सकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने इस पवित्र अवसर से पूर्व जारी अपने संदेश में कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत् 2006 (30 मार्च 1949) को लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

## महंगी हवाई यात्रा पर लोकसभा में गूँज : रूडी ने विमानन क्षेत्र की चुनौतियों को किया उजागर

■ रूडी ने महंगी हवाई यात्रा के लिए ईंधन लागत, राज्यों में एटीएफ कर की असमान दरों और एयरलाइंस की महंगी लीज प्रणाली को जिम्मेदार बताया

रहे सुधारों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास और हवाई यात्रा की सुलभता के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रूडी ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन टिकटों की कीमतें आम नागरिकों को पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। एयरलाइंस को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उच्च ईंधन लागत, भारी कर और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त शुल्क प्रमुख कारण हैं। उन्होंने एनएलआई टर्माइन फ्यूएल (एटीएफ) पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए असमान करों पर चिंता जताई, जिससे किराए में भारी असमानता पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में यह कर 1 फीसदी है, जबकि तमिलनाडु और बिहार में 29

रूडी ने महंगी हवाई यात्रा के लिए ईंधन लागत, राज्यों में एटीएफ कर की असमान दरों और एयरलाइंस की महंगी लीज प्रणाली को जिम्मेदार बताया

इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री को नागरिक विमानन क्षेत्र में किए जा

फीसदी तक जाता है। विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे पर चिंता व्यक्त करते हुए रूडी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण रनवे बंद कर पड़े हैं, जिससे यात्रियों को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के टू नाइन लेफ्ट और टू नाइन राइट रनवे का उदाहरण दिया, जहाँ अर्थ-लैंडिंग की समस्या बनी हुई है।

उड़ान योजना की सराहना करते हुए रूडी ने कहा कि यह छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को बेहतर बुनियादी ढाँचा और सस्ता किराया सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने पायलटों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को अतिरिक्त टर्माइन फ्यूएल (एटीएफ) पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए असमान करों पर चिंता जताई, जिससे किराए में भारी असमानता पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में यह कर 1 फीसदी है, जबकि तमिलनाडु और बिहार में 29

IN LOVING MEMORY OF  
**MAJISA SHANKAR KUMARI DOONGRI**  
It is with profound sorrow we regret to inform you of the passing of  
Majisa Shankar Kumari Doongri on 27th March, 2025.

**BAITHAK**  
from 29th March, 2025- April 6th, 2025  
Daily Time: 5:00 - 6:00 Pm  
Location: 183 Sita Marg, Anand Nagar,  
Sirs Road, Jaipur - 302012

SHE IS LOVINGLY REMEMBERED BY  
Col. Bhawani Singh, Mahipat Singh, Shwina Kumari, Katya Solovetskyaya,  
Dhruv Raj Singh, Yudhishtira Singh, Devisha Kumari Singh,  
Bhim Sen Singh, Mehran Singh, Zoya Singh Bedla Family Doongri Family.